

कृषि नीति निगिरानी और मूल्यांकन 2024

प्रलिस के लयः

[आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, बाज़ार मूल्य समर्थन, न्यूनतम समर्थन मूल्य](#)

मेन्स के लयः

सरकारी खरीद और वतऱरण का प्रभाव, सरकारी नीतयऱँ और पहल, कृषि नीतऱँ और भारतीय कसऱनों पर इसका प्रभाव

[स्रोतः डाउन टू अर्थ](#)

चर्चा में क्यऱँ?

हाल ही में, [आर्थिक सहयोग और विकास संगठन \(OECD\)](#) द्वारा अपनी [2024](#) में बताया गया है कऱँ भारत वर्ष 2023 में अपने कसऱनों पर 120 बलियन अमेरिकी डॉलर का कर लगाएगा, जो 54 देशों में सबसे अधिक है ।

- यह नरऱयात प्रतऱबिंध और शुल्क जैसी सरकारी नीतयऱँ का उद्देश्य उद्देश्यउपभोक्ताओं के लयऱँ खाद्य कीमतों को कम रखना है, लेकनऱँ इससे कृषि क्षेत्र पर भारी वतऱतीय बोझ बढ़ता है ।

OECD की रपऱरट की मुख्य बातें क्यऱँ हैं?

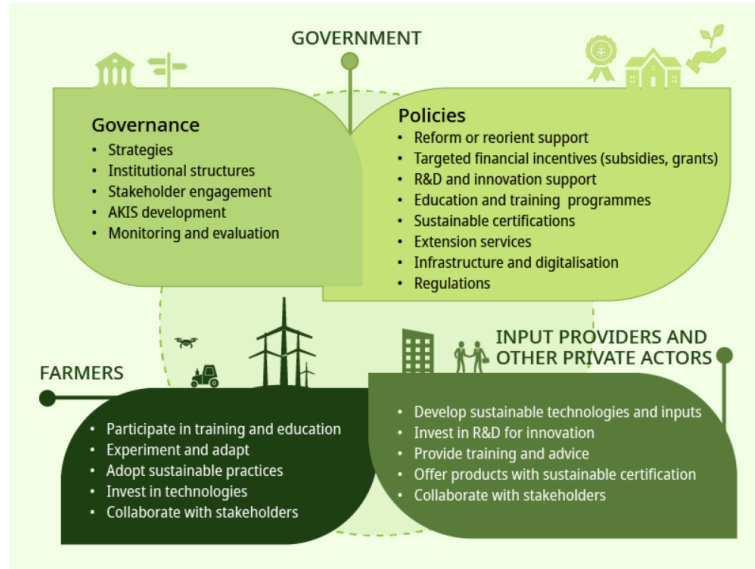
- कृषि में वतऱतीय सहायताः वर्ष 2021 से 2023 तक 54 देशों में कृषि क्षेत्र के लयऱँ कुल सहायता औसतन 842 बलियन अमेरिकी डॉलर प्रतऱँ वर्ष रही है । यद्यपऱँ वर्ष 2021 के शखऱर की तुलना में वर्ष 2022 और 2023 में इसमें गरऱवट आई, फरऱँ भी यह [कोवडऱँ-19 महामारी](#) से पहले के स्तर से काफी अधिक है ।
- वर्ष 2021-23 के बीच बाज़ार मूल्य समर्थन (MPS) में 28 बलियन अमेरिकी डॉलर की गरऱवट आई, लेकनऱँ फरऱँ भी यह कुल समर्थन का एक बड़ा हसऱसा बना रहा ।
 - MPS एक नीतऱगऱत उपाय है जसऱँका उद्देश्य घरेलू बाज़ार में कसऱँ वऱशऱषऱत कृषऱँ उत्पाद की कीमत को एक नऱशऱचऱतऱँ न्यूनतम (सरकार द्वारा नरऱधरऱतऱँ) स्तर पर बनाए रखना है, जसऱँसे घरेलू कीमतों को वऱशऱव कीमतों से ऊपर उठने में मदद मलऱँगी ।
- भारत में कृषऱँ सहायताः वर्ष 2023 में चावल, चीनी, प्याज और तेल रहऱतऱँ चावल की भूसऱँ पर भारत के नरऱयात प्रतऱबिंधों के कारण MPS नकारातऱँक हो गया, जसऱँसे 110 बलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ ।
- परऱगऱमस्वरूप, कसऱँनों को उनकी उपज के लयऱँ उतना मूल्य नहीं मलऱँ जतऱँना इन नीतयऱँ के बनाऱँ मलऱँता, जसऱँसे उनकी आय में उल्लेखनीय कमी आई ।
- वर्ष 2023 में भारत का समग्र बाज़ार मूल्य समर्थन नकारातऱँक था, जसऱँसे 110 बलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ, जसऱँका अर्थ है कऱँ कसऱँनों को उनकी उपज के लयऱँ मूल्य उतना नहीं मलऱँ जतऱँना उनहें इन नीतयऱँ के बनाऱँ मलऱँता था ।
 - भारत में सबसे ज़्यादा नकारातऱँक मूल्य समर्थन था, उसके बाद वयऱतनाम और अर्जेंटीना का स्थान था । वर्ष 2023 में वैश्वकऱँ नकारातऱँक मूल्य समर्थन में भारत का हसऱसा 62.5% था । यह हसऱसा 2000-02 में 61% से बढ़कर 2021-23 में 75% हो गया है, जो भारतीय कसऱँनों पर बढ़ते बोझ को दर्शाता है ।
 - सबसऱँडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से कुल 10 बलियन अमेरिकी डॉलर के सकारातऱँक समर्थन के बावजूद, मूल्य-नरऱशाजनक नीतयऱँ ने इन उपायों को के प्रभाव को कम कर दऱँया ।
- वैश्वकऱँ कृषऱँ चुनौतयऱँः चल रहे संघर्षों (जैसे कऱँ [युक्रेन के खलऱँफ रूस का युद्ध](#) और [मध्य पूरव में अशांतऱँ](#)) ने कृषऱँ बाज़ारों को बाधतऱँ कऱँया है, जसऱँने वऱशऱव रूप से वऱयापार और वैश्वकऱँ आपूर्तऱँ शृंखलाओं को प्रभावतऱँ कऱँया है ।
- चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्तऱँ और गंभीरता, कृषऱँ उत्पादन एवं उत्पादकता के लयऱँ चुनौती बनी हुई है ।
- कुछ देशों के नरऱयात प्रतऱबिंध से कृषऱँ वस्तुओं का अंतरऱँराष्टरीय वऱयापार और अधिक वकऱँत हो गया है ।
- वऱभिन्न देशों में कसऱँनों के बढ़ते वरऱँोध प्रदर्शन से कसऱँनों के आर्थकऱँ एवं सामाजकऱँ संघर्ष पर प्रकाश पड़ता है ।
- वैश्वकऱँ कृषऱँ उत्पादकता की वृद्धऱँ धीमी होने से स्थरऱँता बनाए रखते हुए बढ़ती वैश्वकऱँ खाद्य मांगों को पूरा करना जटलऱँ हो गया है ।
- सरकारें भुगतान को कृषऱँ पद्धतयऱँ से जोड़ रही हैं जसऱँसे भूमऱँ स्वास्थ्य, [जैववऱधऱँता](#) और [स्थरऱँता](#) को समर्थन मलऱँता है, लेकनऱँ परऱयावरणीय

सार्वजनिक वस्तु भुगतान (EPGP) कुल उत्पादक समर्थन का केवल 0.3% है।

◦ EPGP पर्यावरण को लाभ पहुँचाने वाले सार्वजनिक कर्षत्रों (जैसे **जलवायु संरक्षण**) को वित्तपोषित करने का एक तरीका है।

- **दशिया-नरिदेश:** सरकारों को धारणीय उत्पादकता हेतु मापनीय लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है तथा **कुल कारक उत्पादकता (TFP)** एवं **कृषि-पर्यावरण संकेतक (AEIs)** जैसी नगिरानी प्रणालियों में निवेश करना चाहिये।
- TFP द्वारा कृषि इनपुट की दक्षता को मापा जाता है। TFP वृद्धि दर्शाती है कि किसान समान या कम संसाधनों से अधिक उत्पादन कर सकते हैं, जो इसे धारणीय कृषि हेतु एक महत्वपूर्ण उपागम बनाता है।
- **AEIs** से कृषि से होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय प्रभावों और जोखिमों को मापने के साथ उत्पादकों के प्रबंधन के तरीकों का आकलन किया जाता है। ये कृषि के प्रदर्शन एवं इसके अंतरनिहित कारणों को समझाने में भी सहायक हैं।
- **इस रिपोर्ट में उत्पादकता बढ़ाने के क्रम में नवाचार** की आवश्यकता पर प्रकाश डालने के साथ उत्पादन का प्रमुख भाग **धारणीय कृषि पद्धतियों** से जोड़ने का आह्वान किया गया है।

// What governments, farmers and others are doing for sustainable productivity growth



Source: OECD (2024), OECD Agricultural Policy Monitoring and Evaluation: Innovation for Sustainable Productivity Growth (Figure 1.13)

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) क्या है?

- **परिचय:**
 - OECD एक अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना आर्थिक प्रगति व विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिये की गई है।
 - अधिकांश OECD सदस्य राष्ट्र उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं जिनका **मानव विकास सूचकांक (HDI)** बहुत उच्च है एवं उन्हें विकसित देश माना जाता है।
- **स्थापना:**
 - इसके मुख्यालय की स्थापना वर्ष 1961 में पेरिस, फ्रांस में की गई थी तथा इसमें कुल 38 सदस्य देश हैं।
 - OECD में शामिल होने वाले सबसे हालिया देश थे- अप्रैल 2020 में कोलंबिया तथा मई 2021 में कोस्टा रिका।
 - भारत इसका सदस्य नहीं है अपितु एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है।
- **OECD द्वारा जारी रिपोर्ट और सूचकांक:**
 - गवर्नमेंट एट अ ग्लॉस
 - OECD बेटर लाइफ इंडेक्स

भारतीय कृषि नीतियाँ किसानों पर नकारात्मक प्रभाव कैसे डालती हैं?

- **नकारात्मक बाजार मूल्य समर्थन:** भारत की नीतियों के परिणामस्वरूप **किसानों के लिये नकारात्मक बाजार मूल्य समर्थन हुआ है।** वर्ष 2014 से 2016 तक, उत्पादक समर्थन अनुमान (PSE) लगभग -6.2% था, जो नकारात्मक बाजार मूल्य समर्थन (-13.1%) से प्रेरित था।
 - PSE एक मीटरिक है जो उपभोक्ताओं और सरकार से **कृषि उत्पादकों को होने वाले हस्तांतरण के वार्षिक मूल्य को मापता है।**
- **नरियात प्रतिबंध और रोक:** चावल और चीनी जैसी आवश्यक वस्तुओं पर नरियात प्रतिबंध और कोटा लगाने से बाजार तक पहुँच सीमित हो जाती है, जिससे घरेलू कीमतें कम हो सकती हैं।

- नयामक बाधाएँ: **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955** और **कृषि उत्पाद बाज़ार समिति (APMC) अधिनियम 2003** कृषि वस्तुओं के मूल्य निर्धारण, भंडारण और व्यापार पर कठोर नयिम लागू करते हैं।
 - यद्यपि इन अधिनियमों का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य नियंत्रण और कम खरीद मूल्यों के कारण अक्सर कृषि उत्पादों की कीमतें कम हो जाती हैं, जो कभी-कभी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार मूल्यों से भी कम होती हैं, जिससे उत्पादकों पर मूल्य-नरिशाजनक प्रभाव पड़ता है।
- कम न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): MSP का उद्देश्य किसानों की रक्षा करना है, लेकिन कुछ अवधियों के दौरान इसे अंतरराष्ट्रीय मूल्यों से भी कम निर्धारित किया गया है, जिसके कारण किसानों को खुले बाज़ार की तुलना में कम मूल्य प्राप्त हो रहा है।
- वणिणन में अकुशलताएँ: आधुनिक बुनयिदी ढाँचे की कमी और उच्च लेन-देन लागत के कारण किसानों को उनकी उपज के लिये मलिनने वाली कीमतें कम हो जाती हैं, जिससे मूल्य दमन को बढ़ावा मलित्ता है।
- अकुशल संसाधन आवंटन: उर्वरक, सचिाई और बजिली के लिये सबसिडी अल्पकालिक राहत प्रदान करती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, बाज़ार पहुँच और कृषि अनुसंधान में गरिावट जैसे दीर्घकालिक मुद्दों को हल करने में वफिल रहती है, जो अंततः किसानों के लिये सतत् विकास और लाभप्रदता में बाधा उत्पन्न करती है।

कृषिसे संबंधित भारत की पहल

- राष्ट्रीय सतत् कृषि मशिन
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
- कृषि वानिकी पर उप-मशिन (SMAF)
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
- एग्रीसटैक
- डिजिटल कृषि मशिन
- एकीकृत किसान सेवा मंच (UFSP)
- प्रवोत्तर कषेत्तर के लिये जैविक मूल्य शृंखला विकास मशिन (MOVCDNER)

आगे की राह

- नरियात नीतियों में सुधार: नरियात प्रतबिंधों और कोटा को धीरे-धीरे कम करना, बुनयिदी ढाँचे शीत भंडारण, परविहन, प्रसंस्करण) में नविश करना तथा प्रतसिपरद्धा को बढ़ावा देने और उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिये MSP को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार मूल्यों के अनुरूप बनाना।
- बजटीय प्राथमिकताओं में बदलाव: लचीलेपन, स्थिरता, बुनयिदी ढाँचे में सुधार और आपूर्ति शृंखला की अकुशलताओं को कम करने की दशिा में संसाधनों को पुनर्निदेशित करना।
- बेहतर बाज़ार कार्यप्रणाली: समन्वय में सुधार, वखिंडन को कम करने और कषेत्तर की चुनौतियों का समाधान करने के लिये राज्य और केंद्रीय नीतियों के बीच अधिक एकीकरण को बढ़ावा देना।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना: किसानों को उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिये **राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ई-नाम)** जैसे प्रत्यक्ष वणिणन और ई-कॉमर्स को प्रोत्साहित करना, जिससे पारंपरिक बाज़ारों पर नरिभरता कम हो।

?????? ???? ????:

प्रश्न: भारत की कृषि नीतियों का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा कीजिये। नरियात प्रतबिंध और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी नीतियाँ कृषि कषेत्तर को कैसे प्रभावित करती हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

?????????:

प्रश्न: भारत में, नमिनलखिति में से कनिहें कृषि में सार्वजनिक नविश माना जा सकता है? (2020)

1. सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना
2. प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण
3. सामाजिक पूंजी विकास
4. कृषकों को निःशुल्क बजिली की आपूर्ति
5. बैंक प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी
6. सरकारों द्वारा शीतागार सुवधियों को स्थापित करना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 5
- (b) केवल 1, 3, 4 और 5
- (c) केवल 2, 3 और 6

(d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न: भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनजर, फसल बीमा की आवश्यकता की विचारना कीजिये और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी० एम० एफ० बी० वाइ०) की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिये। (2016)

प्रश्न: भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि में आई विभिन्न प्रकारों की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिये। इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार सहायता प्रदान की है? (2017)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation-2024>

